जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:213 दिनांक:14-07-2024 रविवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

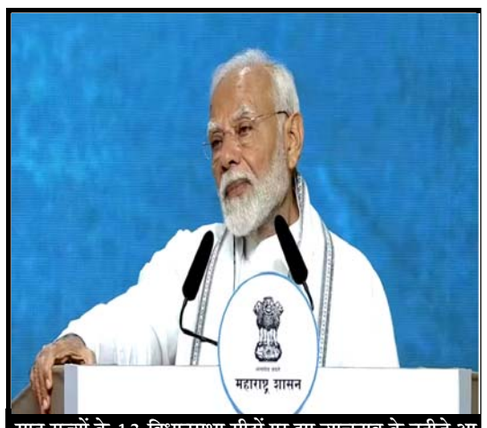

सात राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 10 सीटों पर इंडी गठबंधन को जीत मिली है। दो सीटों पर भाजपा और एक पर निर्दलीय ने जीत का परचम लहराया है। इन चुनावों में सबसे अधिक झटका भाजपा को लगा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मुंबई में सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी 29,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया।

13 सीटों में से आठ पर विपक्षी दलों की जीत, भाजपा को सिर्फ दो सीटें, एक सीट निर्दलीय को मिली

नई दिल्ली(ईएमएस)। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनके परिणाम सामने आ गए हैं, उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जबकि भाजपा को नुकसान हुआ है। 13 में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में आई हैं, जबकि 2 सीटें भाजपा तो एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। उपचुनाव में कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में कमाल किया है, वहीं ममता की पार्टी ने बंगाल में क्लीन स्वीप किया है। जबकि भाजपा ने मध्यप्रदेश और हिमाचल में एक-एक सीट जीती है। उधर, पंजाब की एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है।

मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर, बिहार की रुपौली सीट पर, पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर, पश्चिम बंगाल की रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला विधानसभा सीट पर, हिमाचल की हमीरपुर, देहरा और नलगढ़ सीट पर, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर और तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। उपचुनाव में कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2 और आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती है।

उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया क्लीनस्वीप

देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, दोनों सीट कांग्रेस ने जीत ली हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा उम्मीदवार करतार सिंह भडाना को मात दी है। जबकी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी को 5095 वोटों से हरा दिया है, अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और अब उपचुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुला।

हिमाचल में कांग्रेस का तगड़ा प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, इसमें 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो एक सीट भाजपा के खाते में आई है। देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर ने भाजपा के होशयार सिंह को 9 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है। वहीं नलगढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने भाजपा के कृष्ण लाल ठाकुर को मात दी है। जबकि हमीरपुर की सीट भाजपा के आशीष शर्मा के खाते में गई है, उन्होंने कांग्रेस के डॉ। पुष्पिंदर वर्मा को महज 1433 वोटों से मार्जिन से हराया है।

बंगाल में ममता की पार्टी ने किया क्लीन स्वीप

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, उन्होंने चारों सीटें जीत ली हैं। रानाघाट दक्षिण से टीएमसी के मुकुट मणि अधिकारी ने भाजपा के मनोज कुमार को हराया है। रायगंज से टीएमसी के कृष्णा कल्याणी ने भाजपा के मानस कुमार घोष को, बागदा से टीएमसी की मधूपर्णा ठाकुर ने भाजपा के बिनय कुमार बिस्वास को हराया है।

बिहार की सीट निर्दलीय कैंडिडेट ने जीती

बिहार की रुपौल विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है, इस सीट से निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है। जबकि आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही हैं।

पंजाब की एक सीट आप ने जीती

पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस सीट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बाजी मार ली है, उन्होंने भाजपा कैंडिडेट शीतल अंगुरल को 37 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है।

तमिलनाडु में डीएमके की जीत

तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल की है। डीएमके के अन्नियुर शिवा ञ्जशिवाशनमुगम। ए ने पट्टाली मक्कल काची पार्टी के अन्बुमणि। सी को 67 हजार से अधिक वोटों से हराया है।

अमरवाड़ा में 16 साल बाद जीती भाजपा

अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 16 साल बाद जीत दर्ज की। 2008 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा से भाजपा के प्रेमनारायण ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने गोंगपा के मनमोहन शाह बट्टी को मात्र 437 वोट से हराया था। उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह ने 3027 वोटों से जीत दर्ज की। शनिवार को पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। पहले तीन राउंड तक भाजपा आगे रही। फिर उतार-चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए थे। आखिरी के तीन राउंड में भाजपा को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने दो राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है।

अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए 4 टेबल लगाई गईं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गई। यहां कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कराने वाले कमलेश शाह 2023 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। कमलेश ने भाजपा की मोनिका बट्टी को हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले कमलेश ने भाजपा जॉइन कर ली और 29 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।

किस सीट से कौन जीता
राज्य सीट जीते हारे
-पश्चिम बंगाल
रानाघाट दक्षिण टीएमसी भाजपा
मानिकतला टीएमसी भाजपा
बागदा टीएमसी भाजपा
रायगंज टीएमसी भाजपा
-हिमाचल प्रदेश
देहरा कांग्रेस भाजपा
नलगढ़ कांग्रेस भाजपा
हमीरपुर कांग्रेस भाजपा
-उत्तराखंड
बद्रीनाथ कांग्रेस भाजपा
मंगलौर कांग्रेस बसपा
-मध्य प्रदेश
अमरवाड़ा भाजपा कांग्रेस
-बिहार
रुपौली निर्दलीय जेडीयू
-पंजाब
जालंधर पश्चिम आप भाजपा
-तमिलनाडु
विक्रवंडी डीएमके पीएमके

खाने-पीने की वस्तुएं महंगी होने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी

- मई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 5.9 फीसदी पर

नई दिल्ली (ईएमएस)। खाने-पीने की वस्तुओं के दाम एकाएक बढ़ने से जून में यह भी खुदरा मुद्रास्फी?ति में तेजी देखी गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर चलने वाली यह महंगाई जून में 5.08 फीसदी पर पहुंच गई, जो चार महीने में इसका सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मगर महंगाई की चोट पर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों ने कुछ मरहम लगाया है। मई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) बढ़कर 5.9 फीसदी पर पहुंच गया, जो 7 महीने में इसका सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा। इससे पहले अप्रैल का आईआईपी आंकड़ा घटाकर 5.4 फीसदी कर दिया गया था। आईआईपी का पिछला उच्च स्तर अक्टूबर 2023 में 11.9 फीसदी था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 9.36 फीसदी हो गई, जो मई में 8.69 फीसदी ही थी। इसका कारण अनाज के दामों में 8.75 फीसदी, फलों में 7.15 फीसदी और सब्जियों के भाव में 29.32 तेजी आना रहा। हालांकि दालों के भाव 16.07 फीसदी ही बढ़े, जो मई के मुकाबले कम वृद्धि है मगर अब भी इनके भाव में इजाफा दो अंकों में हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी 4 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर है और ब्याज दरों में कटौती की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। मई में खुदरा मुद्रास्फीति 4.7 फीसदी रही थी। तमाम सर्वेक्षणों के मुताबिक जून में यह 5 फीसदी के करीब रह सकती है। इसलिए जब मुद्रास्फीति 5 फीसदी है और हमारा लक्ष्य उसे 4 फीसदी पर लाने का है तो मुझे लगता है कि ब्याज दरों में कटौती पर बात करने का अभी कोई मतलब नहीं है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 4.6 फीसदी और बिजली का उत्पादन 13.7 फीसदी बढ़ा। मगर खनन क्षेत्र के उत्पादन में थोड़ी सुस्ती दिखी। मई में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 2.5 फीसदी रह गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 8.1 फीसदी थी। कंज्यूमर डयरेबल्स का उत्पादन मई 2024 में 12.3 फीसदी बढ़ा, जबकि मई 2023 में इसमें 1.5 फीसदी की वृद्धि हुई थी।

देश के विकास के दुश्मन जो झूठी कहानियां गढ़ते हैं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुंबई, (ईएमएस)। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे पर थे. मुंबई दौरे के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बड़ा ऐलान किया है. पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत महाराष्ट्र के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार कहकर की. आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास और प्रचार-प्रसार करने का अवसर मिला। इस प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी. इसमें सड़क और रेलवे के अलावा राज्य के युवाओं के कौशल विकास की योजनाएं भी शामिल हैं। राज्य में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा. आपने अखबार देखे होंगे, दो-तीन हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन बोर्ड को मंजूरी भी दे दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 76 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से राज्य में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने विरोधियों पर भी तंज कसा है. उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर गलत कहानी गढ़ने वालों को रोका गया. झूठी कहानी गढ़ने वाले निवेश के दुश्मन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। उनकी नीति युवाओं के साथ विश्वासघात और रोजगार को रोकना है। वे बोर हो रहे हैं. उनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है. पुल बन रहा है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, सड़क बन रही है तो किसी को रोजगार मिलता है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की गति बढ़ रही है, रोजगार की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में और अधिक अवसर पैदा होंगे। एनडीए का विकास मॉडल वंचितों को प्राथमिकता देना है. दशकों तक, वंचितों को दरकिनार कर दिया गया। हम उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं. हमारी नई सरकार ने पक्के मकानों और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। अब तक चार करोड़ लोगों को घर मिल चुका है. निकट भविष्य में तीन करोड़ लोगों के पास पक्के मकान होंगे। इसमें महाराष्ट्र के गरीब, दलित ओबीसी और आदिवासी शामिल हैं। एक अच्छा घर हर परिवार की ज़रूरत नहीं है, यह उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है।मेरा लक्ष्य मुंबई को दुनिया की थिंक-टेक राजधानी बनाना है। पर्यटन में महाराष्ट्र को भारत का नंबर एक राज्य बनना चाहिए। इस जगह पर ऐसे किले हैं जो शिवाजी महाराज की वीरता के गवाह हैं। यहाँ सह्याद्रि की पंक्तियाँ हैं। कोंकण में अथाह समुद्र है। सम्मेलन पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन की संभावना है। महाराष्ट्र भारत में विकास की नई कहानी लिखने का काम कर रहा है। हम इसके गवाह हैं. यह कार्यक्रम इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए है. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक महीने से मुंबई में देश-विदेश के निवेशकों का मेला लगा हुआ है। बड़े और छोटे निवेशकों ने अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। लोग जानते हैं कि केवल एनडीए सरकार ही स्थिरता और स्थायित्व प्रदान कर सकती है। मैंने कहा था कि एनडीए सरकार तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेजी से काम करेगी। मोदी ने कहा कि वह आज ऐसा होते हुए देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य का गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य में प्रचंड धारा है. और राज्य के समृद्ध भविष्य का सपना है। यह एक ऐसा राज्य है जिसने विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। राज्य के पास उद्योग की ताकत है, कृषि की ताकत है, वित्तीय क्षेत्र की ताकत है। इसी ताकत ने मुंबई को देश का वित्तीय केंद्र बना दिया है। अब मोदी ने ऐलान किया कि उनका फोकस महाराष्ट्र को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को लगाई जमकर फटकार कहा- क्या आप खुद को कोर्ट मानते हैं?

नई दिल्ली(ईएमएस)। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अदालत में लंबित एक आवेदन के बावजूद, बिना उचित विचार किए संरक्षित क्षेत्र के पेड़ों को काटने की अनुमति एलजी वीके सक्सेना ने दे दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अदालत की पूर्व अनुमति लिए बिना पेड़ों को काटने के उपराज्यपाल के कदम पर कड़ी नाराजगी जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपराज्यपाल ने पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मान लिया कि दिल्ली सरकार के पास वृक्ष अधिकारी की शक्ति है। यह दुखद स्थिति है कि जो कुछ हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पहले दिन ही बता दिया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं। पीठ ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से तीखे लहजे में सवाल करते हुए कहा, क्या वह खुद को अदालत मानते हैं? इसके अलावा, यह भी पूछा कि क्या डीडीए अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि पेड़ों को काटने के लिए शीर्ष अदालत से अनुमति आवश्यक है। जस्टिस ओका ने कहा, मुझे लगता है कि उपराज्यपाल खुद को अदालत मान रहे हैं। क्या कोई अधिकारी एलजी के पास यह बताने गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता है?

सुप्रीम कोर्ट सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए संरक्षित वन क्षेत्र में 1,100 पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष के खिलाफ स्वतःसंज्ञान से अवमानना कार्यवाही की सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत ने मामले में उपराज्यपाल की संलिप्तता को छिपाने के प्रयासों की भी निंदा की और कहा कि सुनवाई के पहले दिन ही उसे यह बता दिया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल ने पहले ही पेड़ों की कटाई के निर्देश जारी किये थे। पीठ ने जोर देकर कहा कि वीके सक्सेना सहित सभी संबंधित पक्षों ने गलतियां की हैं और स्पष्टीकरण के लिए अदालत में आने के बजाय इन त्रुटियों को छिपाने का विकल्प चुनने के लिए उनकी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या उसने उपराज्यपाल की अनुमति के आधार पर पेड़ों को काटने का निर्णय लिया था या कोई स्वतंत्र निर्णय भी लिया गया था? इसने पेड़ों की कटाई का काम करने वाले ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया, जिसमें उसे अदालत को यह बताने के लिए कहा गया कि किसके निर्देश पर उसने यह कार्रवाई की है।यह मामला डीडीए द्वारा सैकड़ों से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा है, जो अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है, जिसके अनुसार ऐसी कार्रवाई करने से पहले अदालत से अनुमति लेना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर डीडीए ने दक्षिणी रिज क्षेत्र में लगभग 1,100 पेड़ काटे हैं। पीठ ने कहा, हमें इस बात से परेशानी है कि हर किसी ने गलती की है। पहले दिन सभी को अदालत में आकर कहना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है लेकिन लीपापोती चलती रही।

विकास की सूची में केरल और उत्तराखंड अव्वल है पर बिहार, झारखंड और नागालैंड पिछड़े

नई दिल्ली(ईएमएस)।जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उत्तराखंड और केरल में अच्छा काम हुआ है। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंचे है। इसके बाद तमिलनाडु 78 और गोवा 77वां का स्थान है। जबकि उत्तर प्रदेश को 67 अंक मिले हैं। उधर, फिसड्डी राज्यों की बात करें तो बिहार 57, झारखंड 62 और नगालैंड 63 अंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली शीर्ष पांच में शामिल किए गए हैं।

आयोग की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में भी मदद मिली है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सतत विकास लक्ष्य 2023-24 सूचकांक की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि बीते दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। दो राज्यों को गरीबी उन्मूलन पर एसडीजी-1 प्राप्त करने के लिए सुधार करने की जरूरत है। इनमें बिहार और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का उद्देश्य राज्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाकर और उसमें सुधार करना है। इसके साथ ही राज्यों को विकास के रास्ते पर लाना है। क्योंकि विकास के रास्ते ही लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन संभव है। भारत का समग्र एसडीजी सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया है जो 2020-21 में 66 था। गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक, कामकाज के अवसर मुहैया कराने, आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई और जमीनी इलाकों में जीवन पर महत्वपूर्ण प्रगति के चलते यह सुधार देखने को मिला है।

बिहार में बिजली गिरने से 21 मौतें रोहतास वाटरफॉल में 6 डूबते बचे

नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई हैं। राज्य की नदियां उफान पर हैं। भागलपुर में गंगा और कोसी से कटाव हो रहा है। कई घर नदी में समा चुके हैं। कुछ लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।

रोहतास के मां तुतला भवानी धाम वाटरफॉल में शनिवार सुबह पानी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। 6 लोग पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। उन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया।

उधर, उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे जिलों बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज के करीब 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में हैं। शाहजहांपुर में दिल्ली-लखनऊ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है। बलरामपुर में प्राइमरी स्कूल में 3 फीट तक पानी भरा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे सडक़, रेल और एयर ट्रैफिक सर्विसेस प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली के भी कुछ इलाकों में शुक्रवार देर रात शनिवार सुबह तेज बारिश देखने को मिली। यहां आज भी बारिश होने के आसार हैं।

आरबीआई के अनुसार, पिछले चार वर्षों में देश में आठ करोड़ नयी नौकरियां उपलब्ध हुईं - पीएम

मुंबई (ईएमएस)। पीएम नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि

पिछले तीन से चार वर्षों में देश में आठ करोड़ नयी नौकरियां उपलब्ध हुईं।

मोदी मुंबई के गोरेगांव उपनगर में क्षेत्र में सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में 29,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

पीएम मोदी ने कहा, ''आरबीआई ने हाल में रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन-चार वर्षों में लगभग आठ करोड़ नयी नौकरियां पैदा हुई हैं। इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी खबरें फैलाने वालों को चुप कर दिया है।

उन्होंने कहा, ''देश में कौशल विकास और रोजगार की जरूरत है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई और उसके आसपास की आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से शहर के आस-पास के इलाकों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा, ''छोटे और बड़े निवेशकों ने हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। पीएम ने कहा, ''मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बनाना और मुंबई को वैश्विक फिनटेक राजधानी बनाना है।

राजस्थान में लापता हो रहीं लड़कियों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, कानून बनाने की हो रही तैयारी

जयपुर(ईएमएस)। राजस्थान में आए दिन लड़कियां लापता हो रही है। ये कहां जा रहीं हैं और कौन ले जा रहा है इसको लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है। राज्य की बेटियों की सुरक्षा को लेकर विधानसभा में भी चिंता जाहिर की गई है। सदन में मौजूद सभी विधायकों ने एक ही सुर में कहा कि ये मसला बेहद गंभीर है और इसका स्थाई समाधान निकलना चाहिए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस पर हम सबकों गंभीरता से सोचने की जरुरत है।

विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में यह मामला उठा। इस दौरान प्रेम विवाह और घर से भगाने के मामलों का भी जिक्र हुआ। मारवाड़ जंक्शन के विधायक केसाराम चौधरी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पिछले दिनों में उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अकेले उनके विधानसभा क्षेत्र में ही 475 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में नाबालिग बच्चियों के लापता होने से जुड़े 122 मामले दर्ज हुए हैं। जबकि बालिग लड़कियों के 372 मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों पुलिस की ओर से ढूंढकर लाई गई कई बालिग और नाबालिग लड़कियों ने अपने माता-पिता को ही पहचान से इनकार कर दिया। केसाराम चौधरी बोले यह मामला गंभीर है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। कैसे इसमें सुधार हो सकता है? अगर कानून बनाने की जरूरत हो तो उस पर भी गौर किया जाए। विधायक केसाराम की इस चिंता को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गंभीर मामला बताते हुए कहा कि हम सबको आपस में इस पर बात करके समाधान खोजना चाहिए। इस दौरान कुछ विधायकों ने इसका कारण

लाजपत नगर में दो गुटों के बीच चलीं ताबड़तोड़ गोलियां

नई दिल्ली : दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लाजपत नगर इलाके के एच ब्लॉक में 18 वर्षीय अभिषेक उर्फ कात्या को गोली मार दी गई, गोली उसके घुटने में लगी है जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिला पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि गोली अभिषेक तनेजा नामक युवक ने मारी है, पुरानी रंजिश में।

जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला ,उपराज्यपाल को दी दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां

दिल्ली/श्रीनगर (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी।

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे।

राज्य में सरकार कोई रहे, ताकत एलजी के पास

जम्मू-कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजा फैसले के बाद राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेंगी। इसके लिए संशोधित नियमों में दो पॉइंट जोड़े गए। पहला 42ए के तहत कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत 'पुलिस', 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'अखिल भारतीय सेवा' और 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। दूसरा 42बी अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी

केंद्र के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा- एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टाम्प ष्टरू से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।

5 अगस्त, 2019 को पारित हुआ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम

5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019) संसद में पारित किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला- जम्मू-कश्मीर और दूसरा- लद्दाख। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दर्जा दिया था। जम्मू-कश्मीर जून 2018 से केंद्र सरकार के शासन के अधीन है। 28 अगस्त, 2019 को गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए सबसे पहले नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के कार्यों को परिभाषित किया गया।

जनता ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को नकारा - सुखविंद्र सिंह सुक्खू

शिमला (ईएमएस)। हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उप-चुनाव में दो सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने धनबल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के मतदाताओं के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश की जनता ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि देहरा में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी पार्टी आने वाले 50 साल में खरीद-फरोख्त की राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और प्रदेश से यह संदेश पूरे देश की राजनीति में जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 28 फरवरी 2024 को प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर चुनी हुई सरकार को गिराने का षडयंत्र रचा गया, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या एक बार फिर 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार-बार भाजपा की दो सरकारें बनाने की बातें करते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन लोट्स विफल हो गया है। जनता से सबक मिलने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के लोगों को ठगने और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन निर्दलीय विधायकों ने यह उप-चुनाव प्रदेश की जनता पर थोपा। अगर वह प्रदेश सरकार से नाराज थे तो विधानसभा में भाजपा के साथ बैठकर विपक्ष को अपना समर्थन देते। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक सरकार को गिराने के षडयंत्र के तहत एक माह तक प्रदेश से बाहर रहे और अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठे। उनके इसी रवैये के कारण उप-चुनाव हुए, लेकिन जनता ने अब उन्हें करारा जवाब दिया है। यह जीत उ

जन हितैषी

25 जून संविधान बचाओ या हत्या दिवस?

केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करते हुए, अधिसूचना जारी की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर गजट नोटिफिकेशन की जानकारी देकर, नए विवाद को जन्म दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ के तौर पर लड़ा था। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने संविधान बचाओ को लेकर मतदाताओं से वोट मांगे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों और विचारकों द्वारा संविधान में संशोधन करने के लिए 400 सीटों का नारा दिया था। चुनाव के पहले ही नेशनल अखबारों में संविधान में परिवर्तन करने के लिए बड़े-बड़े लेख छापे गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव अभियान में 400 पार का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 242 सीट और एनडीए गठबंधन को 293 सीट मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीटें हासिल नहीं हुई हैं। चुनाव परिणाम के बाद संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर सदन में संविधान की शपथ ली। उसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ने लगा था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद जो पहला प्रस्ताव पारित किया गया, वह आपातकाल की निंदा को लेकर था। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। उसमें भी आपातकाल का उल्लेख किया गया। उसके बाद से स्पष्ट होने लगा था, संविधान का जवाब आपातकाल से देकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में जो आपातकाल के दौरान जेल में थे, वो आज इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। उनके बीच में फूट डालने के लिए आपातकाल को निशाना बनाया गया है। इंदिरा गांधी ने 1975 में जो आपातकाल लगाया था। संविधान में आपातकाल लगाने का अधिकार सरकार को था। उस समय की संसद ने इसे बहुमत से पास किया था। जब तक आपातकाल लगा था। तभी तक आपातकाल के विशेष अधिकार सरकार को मिले हुए थे। संविधान में अभी भी तीन किस्म के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। सीमा पार से युद्ध की आशंका हो। आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति हो, अथवा आर्थिक कारणों से वर्तमान में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ। वैसे ही फिर से सारे संवैधानिक अधिकार मूल स्वरूप में वापस आ गए थे। अभी अघोषित आपातकाल की बात हो रही है। सबसे पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने 2016 में अघोषित आपातकाल की बात कही थी। पिछले वर्षों में जिस तरह से संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। विपक्षी दलों को आरोपों के आधार पर कई महीनों और वर्षों तक जेल में रखा जा रहा है। ईड़ी के विशेष कानूनी प्रावधान तस्करों और आतंकवादियों के लिए बनाये गये थे। उसका उपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद करके रखने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान सरकार भी संविधान में लगातार संशोधन कर रही है। जिन संशोधन को सदन में बहुमत से अनुमति मिल जाती है, वे कानूनी रूप से लागू हो जाते हैं। उसका पालन आम जनता, कार्यपालिका और न्यायपालिका को करना पड़ता है। संविधान 1975 में भी खत्म नहीं हुआ था। संविधान 2024 में भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करना एक तरह से संविधान का मजाक उड़ाना है। संविधान अभी भी अस्तित्व में है। हत्या का मतलब होता है, संविधान के वजूद का खत्म हो जाना। संविधान की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका का है। संविधान के जो प्रावधान हैं। विधायिका या कार्यपालिका जब संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाकर कानून बनाती है। कार्यपालिका संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों की अनदेखी कर मनमानी करती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का दायित्व है, कि वह संविधान की रक्षा करें। न्यायपालिका के आदेश को सभी को मानना पड़ता है। संविधान पहले भी था। संविधान अब भी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और कुछ नेताओं द्वारा संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन करने की मुहिम लोकसभा 2024 चुनाव के पहले चलाई गई थी। 400 पार का नारा संविधान में संशोधन करना है, इसीलिए दिया गया था। चुनाव के दौरान जब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। तब भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती समझ में आई। और उन्होंने संविधान की रक्षा करने की बात कही। संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार भाजपा को मिले। जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 240 सीटों पर जीत मिली। जिस तरह की चुनौती अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को मिल रही है। 23 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है, कि संविधान हत्या दिवस घोषित करके पक्ष और विपक्ष के बीच में एक नया विवाद सुनयोजित रणनीति के रूप में शुरू किया गया है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राम मंदिर निर्माण का कोई लाभ नहीं मिला। कुछ ऐसी ही स्थिति संविधान विवाद को लेकर भाजपा सोच रही है। संविधान विवाद का भाजपा और सरकार को राजनीतिक रूप से फायदा होगा। यह उनकी बड़ी भूल है। नई पीढ़ी जिसने ना तो आपातकाल देखा, नाही आपातकाल के बारे में कुछ जानती है। 65 फीसदी भारतीय नागरिक जरूर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले से परेशान हैं। मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के विवाद सरकार के काम आने वाले नहीं हैं। आपातकाल का मामला तो खुद मोदी सरकार के गले पड़ रहा है। घोषित और अघोषित आपातकाल की बात वर्तमान सरकार के दौर में हो रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उल्टे समय आने पर नुकसान जरूर हो सकता है।

क्या सचमुच हमारा संविधान मर चुका है?

भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी कर 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। सरकार इस तरह का क्या,किसी भी तरह का कोई भी फैसला कर सकती है। इस फैसले का अंधभक्त स्वागत करेंगे और विपक्ष शायद विरोध ,लेकिन एक आम नागरिक और नामालूम लेखक होने के नाते मै इस फैसले को हास्यास्पद कह रहा हूँ ,क्योंकि क्या सचमुच हमारा संविधान मर चुका है ?

भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी कर 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। सरकार इस तरह का क्या,किसी भी तरह का कोई भी फैसला कर सकती है। इस फैसले का अंधभक्त स्वागत करेंगे और विपक्ष शायद विरोध ,लेकिन एक आम नागरिक और नामालूम लेखक होने के नाते मै इस फैसले को हास्यास्पद कह रहा हूँ ,क्योंकि यदि देश का संविधान मर चुका होता तो बीते 9 जून को किस संविधान की कसम खाकर माननीय लोगों ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है ?

संविधान एक लिखित प्रज्ञा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा वेद,सबसे बड़ा पुराण,सबसे बड़ी किंवदंती। यदि ये मर गया होता तो 1975 के बाद देश में लोकतंत्र बचता ही नहीं। देश में ढाई साल की खिचड़ी सरकार के बाद देश की जनता ने 1980 में उसी कांग्रेस को ,उन्हीं इंदिरा गाँधी को दोबारा देश की सत्ता सौंपी जिन्हें संविधान की हत्या का दोषी मानने वाली आज की सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। क्योंकि अब मौजूदा सरकार पर ही संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप आयद किया जा चुका है।

चूंकि मै कानून का छात्र रहा हूँ इसलिए मैंने देश के संविधान को न केवल पाठयक्रम में अपितु सामान्य तौर पर अनेक बार पढ़ा है। मैंने संविधान का इस्तेमाल देश सेवा की झूठी कसमें खाने के लिए कभी नहीं किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आपातकाल की घोषणा संवैधानिक नियमों के तहत की गई थी लेकिन आपातकाल के दौरान 1971 में पारित आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरूपयोग किया गया था

देश में आपातकाल के हटने के फौरन बाद बनी खिचड़ी सरकार ने इस अधिनियम को 1979 में समाप्त किया गया था और संविधान के 44वें संसोधन के ज़रिए संवैधानिक आपातकाल को लागू करने के लिए इतने उपबंध जोड़ दिये गये जिससे आपातकाल लागू करना असंभव सा हो गया। भाजपा यदि लोकसभा चुनाव में 400 पार कर जाती तो आपातकाल लागू करने का प्रावधान फिर संविधान में जोड़ा जा सकता था। लेकिन ये हो न सका।

संविधान हत्या दिवस मनाने वाले देश में बिना आपातकाल की घोषणा किये आपातकाल जैसा माहौल बनाये हुए हैं लेकिन औपचारिक रूप से आपातकाल की घोष्णा नहीं कर पा रहे हैं,हालाँकि मंशा इंदिरा गाँधी की ही तरह आपातकाल लागू करने की है। दुनिया को पता है कि भारत में से 2014 से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। हकीकत ये है कि हमारी मौजूदा सरकार संविधान से खिलवाड़ के आरोपों से मुक्ति पाने के लिए पचास साल बाद एक बार फिर आपातकाल का हौवा खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है ,लेकिन उल्लू टेढ़ा का टेढ़ा है। कभी-कभी मुझे लगता है कि सरकार भाजपा सांसद कंगना रनौत की बहुप्रतिक्षित फिल्म इमरजेंसी का लगातार असंवैधानिक तरीक़े से प्रमोशन पूरी सरकार कर रही है। इस फील्म की रिलीज लोकसभा चुनाव की वजह से टल गयी थी। इमरजेंसी यानि आपातकाल पर पहले भी किस्सा कुर्सी का और आंधी जैसी फ़िल्में बन चुकीं है।

यदि आप भूले न हों तो माननीय एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं क्योंकि भाजपा संसदीय दल के नेता का औपचारिक चुनाव प्रतिक्षित हैं। अपने ही दल के संविधान की हत्या कर सत्ता में आये मोदी जी संविधान हत्या दिवस शब्द का चयन कर वास्तव में संविधान का क्या हाल वे खुद करना चाह रहे थे । जो एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक परंपराओं के तहत विपक्ष को नहीं देना चाहता है वह निहायत ही बेशर्मी से संविधान हत्या दिवस मना सकते हैं। संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए राजपत्र का सहारा लेना ही एक नासमझी है । यदि सचमुच माननीय ने एक मरे हुए संविधान की शपथ ली है तो उन्हें हत्या जैसे हिंसक शब्द का इस्तेमाल करने और संविधान का अनादर करने से कोई नहीं रोक सकता ।

संविधान की हत्या तो नहीं लेकिन उसके साथ खिलवाड़ की जितनी कोशिशें आज हो रहीं हैं। उतनी कोशिशे आपातकाल के 19 महीनों में भी नहीं हुईं। अन्यथा मनु स्मृति को पाठयक्रम में शामिल करने का असफल प्रयास नहीं किया जाता। आप खुद पता कर सकते हैं कि कौन महापुरुष मनु स्मृति को संविधान के स्थान पर लाना चाहते थे। दरअसल भाजपा को जो काम करना है उसे सरकार कर रही है। केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष द्वारा संविधान पर खतरे की मुहिम चलने से आहत है। विपक्ष ने खासतौर पर कांग्रेस ने जनता को संविधान के साथ हो रहे खिलवाड़ के प्रति जाग्रत करने में कामयाबी हासिल की है ,इसी से भयभीत होकर केंद्र की सरकार ने एक बचकाना संकल्प ले लिया है।

राज पत्र या किसी अध्यादेश की भाषा कैसी हो इसका भान शायद सरकार को नहीं है । सरकार के पास भाषाविद हैं ही नहीं हैं , या हैं तो वे अधिकांश संघ के प्रचारक हैअन जो ठकुरसुहाती करने में दक्ष हैं। यदि ऐसा न होता तो सरकार संविधान हत्या दिवस मनाने की भूल न करती। मेरा तो सुझाव है कि सरकार अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ साहित्यकारों के समूह को रखे ताकि भाषा की मर्यादा भाषण और अधिनियमों के निर्माण में भी दिखे।

मै आपातकाल का समर्थक न कल था ,न आज हूँ और न कल रहूंगा । मेरी स्पष्ट धारणा है कि आपाताकाल कांग्रेस के तबके कुछ उत्साहीलालों की वजह से बदनाम हुआ,क्योंकि उन लोगों ने संवैधानिक अधिकारों और शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस लिहाज से कांग्रेस ने संविधान की हत्या नहीयदि देश का संविधान मर चुका होता तो बीते 9 जून को किस संविधान की कसम खाकर माननीय लोगों ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है ?

संविधान एक लिखित प्रज्ञा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा वेद,सबसे बड़ा पुराण,सबसे बड़ी किंवदंती। यदि ये मर गया होता तो 1975 के बाद देश में लोकतंत्र बचता ही नहीं। देश में ढाई साल की खिचड़ी सरकार के बाद देश की जनता ने 1980 में उसी कांग्रेस को ,उन्हीं इंदिरा गाँधी को दोबारा देश की सत्ता सौंपी जिन्हें संविधान की हत्या का दोषी मानने वाली आज की सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। क्योंकि अब मौजूदा सरकार पर ही संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप आयद किया जा चुका है।

चूंकि मै कानून का छात्र रहा हूँ इसलिए मैंने देश के संविधान को न केवल पाठयक्रम में अपितु सामान्य तौर पर अनेक बार पढ़ा है। मैंने संविधान का इस्तेमाल देश सेवा की झूठी कसमें खाने के लिए कभी नहीं किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आपातकाल की घोषणा संवैधानिक नियमों के तहत की गई थी लेकिन आपातकाल के दौरान 1971 में पारित आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरूपयोग किया गया था

देश में आपातकाल के हटने के फौरन बाद बनी खिचड़ी सरकार ने इस अधिनियम को 1979 में समाप्त किया गया था और संविधान के 44वें संसोधन के ज़रिए संवैधानिक आपातकाल को लागू करने के लिए इतने उपबंध जोड़ दिये गये जिससे आपातकाल लागू करना असंभव सा हो गया। भाजपा यदि लोकसभा चुनाव में 400 पार कर जाती तो आपातकाल लागू करने का प्रावधान फिर संविधान में जोड़ा जा सकता था। लेकिन ये हो न सका।

संविधान हत्या दिवस मनाने वाले देश में बिना आपातकाल की घोषणा किये आपातकाल जैसा माहौल बनाये हुए हैं लेकिन औपचारिक रूप से आपातकाल की घोष्णा नहीं कर पा रहे हैं,हालाँकि मंशा इंदिरा गाँधी की ही तरह आपातकाल लागू करने की है। दुनिया को पता है कि भारत में से 2014 से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। हकीकत ये है कि हमारी मौजूदा सरकार संविधान से खिलवाड़ के आरोपों से मुक्ति पाने के लिए पचास साल बाद एक बार फिर आपातकाल का हौवा खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है ,लेकिन उल्लू टेढ़ा का टेढ़ा है। कभी-कभी मुझे लगता है कि सरकार भाजपा सांसद कंगना रनौत की बहुप्रतिक्षित फिल्म इमरजेंसी का लगातार असंवैधानिक तरीक़े से प्रमोशन पूरी सरकार कर रही है। इस फील्म की रिलीज लोकसभा चुनाव की वजह से टल गयी थी। इमरजेंसी यानि आपातकाल पर पहले भी किस्सा कुर्सी का और आंधी जैसी फ़िल्में बन चुकीं है।

यदि आप भूले न हों तो माननीय एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं क्योंकि भाजपा संसदीय दल के नेता का औपचारिक चुनाव प्रतिक्षित हैं। अपने ही दल के संविधान की हत्या कर सत्ता में आये मोदी जी संविधान हत्या दिवस शब्द का चयन कर वास्तव में संविधान का क्या हाल वे खुद करना चाह रहे थे । जो एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक परंपराओं के तहत विपक्ष को नहीं देना चाहता है वह निहायत ही बेशर्मी से संविधान हत्या दिवस मना सकते हैं। संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए राजपत्र का सहारा लेना ही एक नासमझी है । यदि सचमुच माननीय ने एक मरे हुए संविधान की शपथ ली है तो उन्हें हत्या जैसे हिंसक शब्द का इस्तेमाल करने और संविधान का अनादर करने से कोई नहीं रोक सकता ।

संविधान की हत्या तो नहीं लेकिन उसके साथ खिलवाड़ की जितनी कोशिशें आज हो रहीं हैं। उतनी कोशिशे आपातकाल के 19 महीनों में भी नहीं हुईं। अन्यथा मनु स्मृति को पाठयक्रम में शामिल करने का असफल प्रयास नहीं किया जाता। आप खुद पता कर सकते हैं कि कौन महापुरुष मनु स्मृति को संविधान के स्थान पर लाना चाहते थे। दरअसल भाजपा को जो काम करना है उसे सरकार कर रही है। केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष द्वारा संविधान पर खतरे की मुहिम चलने से आहत है। विपक्ष ने खासतौर पर कांग्रेस ने जनता को संविधान के साथ हो रहे खिलवाड़ के प्रति जाग्रत करने में कामयाबी हासिल की है ,इसी से भयभीत होकर केंद्र की सरकार ने एक बचकाना संकल्प ले लिया है।

राज पत्र या किसी अध्यादेश की भाषा कैसी हो इसका भान शायद सरकार को नहीं है । सरकार के पास भाषाविद हैं ही नहीं हैं , या हैं तो वे अधिकांश संघ के प्रचारक हैअन जो ठकुरसुहाती करने में दक्ष हैं। यदि ऐसा न होता तो सरकार संविधान हत्या दिवस मनाने की भूल न करती। मेरा तो सुझाव है कि सरकार अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ साहित्यकारों के समूह को रखे ताकि भाषा की मर्यादा भाषण और अधिनियमों के निर्माण में भी दिखे।

मै आपातकाल का समर्थक न कल था ,न आज हूँ और न कल रहूंगा । मेरी स्पष्ट धारणा है कि आपाताकाल कांग्रेस के तबके कुछ उत्साहीलालों की वजह से बदनाम हुआ,क्योंकि उन लोगों ने संवैधानिक अधिकारों और शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस लिहाज से कांग्रेस ने संविधान की हत्या नहीं की अपितु संविधान का अपमान किया और उसकी सजा जनता ने 1977 में कांग्रेस को सत्ताच्युत कर दे दी। अब पचास साल बाद भी आपातकाल की गागरोनी गाना सत्तारूढ़ दल और सरकार के सबसे बड़े घटक के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है।

सरकार के हास्यास्पद फैसले का प्रतिकार करने में कांग्रेस शायद पिछड़ गयी लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखा प्रहार लिया। उन्होंने कहा की -बीजेपी बताए कि वह अपने काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनेगी ? अखिलेश ने एक्स पर लिखा-30 जनवरी को 'बापू हत्या दिवस' व 'लोकतंत्र हत्या दिवस' के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी।

मुझे अंदेशा है कि भारत सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला विपक्ष के संविधान बचाओ नारे के काट के रूप में लाया गया है ,लेकिन ये दांव उलटा भी पड़ सकता है। बहरहाल देश के सामने एक नया जुमला उछाला जा चुका है। आइये हम सब तेल देखें और तेल की धार भी देखें। अगले साल आप 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाये या न मनाएं ,ये आपके विवेक पर निर्भर करता ह। यदि सरकार तब तक बनी रही तो सरकार तो ये दिवस मनाकर मानेगी।(लेखक-राकेश अचल/ ईएमएस)

परंपरागत सेवाओं के विकल्प की आवश्यकता

महामारी के संघर्ष से उत्पन्न वैकल्पिक साधनों को बाजार जिस तरह हथियार की तरह दुरुपयोग करता है उसे हमने कोरोना कल में अनुभव किया शायद आर्थिक मंदी से उबरने की दिशा में यह वैश्विक रणनीति का एक षडयंत्र हो। इसने मोबाइल क्रांति को इतना प्रश्रय दिया कि यह जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया । आधार, समग्र, आयुष्मान, पुलिस वेरीफिकेशन लाइसेंस केवाईसी अपडेशन शैक्षणिक और शासकीय संस्थाओं , बैंकिंग, रेलवे , वाणिज्यिक ,यातायात आयकर परिवहन खरीददारी जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह कोरोना अपरूप की तरह पसर गया , जिसने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल के विकास लक्ष्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को शिकार बनाया। बिचौलियों के रूप में बैंक सेवा केंद्रों ने इन निरक्षर ,बेसहारा, असहाय पीड़ित नागरिकों का हर संभव शोषण किया। वहीं मौजूदा चुनावी वर्ष में निशुल्क मोबाइल रिचार्ज के नाम पर फेक वायरल संदेश राजनीतिक दलों के लाभ का माध्यम बना। एडीआर द्वारा बामशक्कत जारी चुनावी चंदे के नाम पर हजारों करोड़ की वसूली की पुष्टि के फलस्वरूप मोबाइल सेवा प्रदाताओं से जुड़ी कंपनियों को बिना किसी नियमन के अप्रत्शित तरीके से टेरिफ प्लान हाइक की अनुमति दी गई।

इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के महा सचिव रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेल फोन उपभोक्ताओं की जेब से 34,824 करोड़ रुपये की वसूली की अनुमति क्यों दी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ''हिंदुस्तान के सेल फोन मार्केट में रिलांयस जियो के 48 करोड़, एयरटेल के 39 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ 37 लाख ग्राहक हैं। ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार सेल फोन कंपनियां अपने हर सेल फोन ग्राहक से 152.55 पैसे प्रति माह कमाती हैं।''

इसके वावजूद 27 जून को रिलायंस जियो ने अपने रेट 12 प्रतिशत से 27 प्रतिशत बढ़ा दिए। 8 जून को एयरटेल ने अपने रेट 11 प्रतिशत से 21 प्रतिशत बढ़ा दिए। 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रेट 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत बढ़ा दिए । इस फैसले से साफ है कि तीनों कंपनियों ने सलाह कर सिर्फ 72 घंटे में सेल फोन की शुल्क दर बढ़ाने की घोषणा की। अगर सेल फोन कंपनियों का औसत आय की बात करें तो रिलायंस जियो के हर यूजर पर 30.51 रुपए की बढ़त हुई है। यानी सालाना 17,568 करोड़ रुपये अतिरिक्त वूसल किए जाएंगे। एयरटेल के ग्राहकों पर 22.88 रुपये की बढ़त हुई है। यह सालाना 10,704 करोड़ रुपये होगा। वोडाफोन के उपभोक्ता पर 24.40 रुपये की बढ़त हुई है इस प्रकार अपने यूजरों से यह कंपनियां प्रतिवर्ष 6,552 करोड़ रुपये वूसलेगी।

ऐसी स्थिति में जनहितैषी के रूप में तीसरी बार सत्तासीन मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन उपभोक्ताओं पर लगभग 35 हजार करोड़ रुपए का बोझ डालने से पहले कोई स्वस्थ पहल नहीं की। अन्यथा यह कैसे संभव है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपना टैरिफ 15-20 प्रतिशत बढ़ा दें, जबकि उनका इंवेस्टमेंट, कस्टमर बेस आदि सब अलग है।अत्याधुनिक विकास के नाम पर बीआरटीएस कॉरिडोर , स्मार्ट ई-साइकिल ,स्मार्ट सिटी जलसोधन विद्युतीकरण जैसी जीवनोपयोगी योजना के हश्र के बावजूद एक बड़ा वर्ग मंहगाई वृद्धि की तर्ज पर इसका पक्षधर हो सकता है लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे भीड़ तंत्र के कानून से लोगों को आगाह करते थे । उनका मानना था कि सरकार के दो रूपों लोकतंत्र और स्वतंत्रता में से लोकतंत्र को जिंदा बचाए रखना मुश्किल है।लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं होना चाहिए बल्कि वहां समाज के लोगों की ऐसी नुमाइंदगी का शासन होना चाहिए जहां कम से कम उनकी आवाज पहुंच सके।

केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि विकास की दौड़ में पिछड़े लोगों के हित में ई-कारोबार में मोबाइल ओटीपी की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए परंपरागत कार्य शैली को भी बनाए रखें। (लेखक- राकेश कुमार वर्मा/ ईएमएस)

पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव

विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नये आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि , औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहाँ प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है प्रगति की दौड़ में आज का मानव इतना अंधा हो गया है कि वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी करने को तैयार है।पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है।इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन् 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया।इसके पश्चात सन् 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गये। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन-चक्र भी समाप्त हो जायेगा।पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव हैं, जो अतीव घातक हैं, जैसे आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवांशिक प्रभाव, वायुमण्डल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण आदि ऐसे घातक दुष्प्रभाव हैं। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नये रोगों से आक्रान्त होना आदि देखे जा रहे हैं। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है।अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत 'जल' को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू, गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं, परिणामस्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लेते हैं जिसमें उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल व सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं जिनके सेवन से अवशिष्ट जीवननाशी रसायन मानव शरीर में पहुंच कर खून को विषैला बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय-समय पर देते रहें। अच्छे व मंहगें ब्रांड के कपड़े पहनाने से कहीं महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारा भविष्य व उनकी पूंजी है।आज वायु प्रदूषण ने भी हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक चुनौती है। माना कि आज मानव विकास के मार्ग पर अग्रसर है परंतु वहीं बड़े-बड़े कल-कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों से और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं, जलाने वाला हाइकोक, ए.सी., इन्वर्टर, जेनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। वस्तुतः वायु प्रदूषण सर्वव्यापक हो चुका है।सही मायनों में पर्यावरण पर हमारा भविष्य आधारित है, जिसकी बेहतरी के लिए ध्वनि प्रदूषण को और भी ध्यान देना होगा। अब हाल यह है कि महानगरों में ही नहीं बल्कि गाँवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग करने लगे हैं। बच्चे के जन्म की खुशी, शादी-पार्टी सभी में डी.जे. एक आवश्यकता समझी जाने लगी है। जहां गाँवों को विकसित करके नगरों से जोड़ा गया है। वहीं मोटर साइकिल व वाहनों की चिल्ल-पों महानगरों के शोर को भी मुँह चिढ़ाती नजर आती है। औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण-शक्ति का ह्रास होता है। ध्वनि प्रदूषण का मस्तिष्क पर भी घातक प्रभाव पड़ता है।(लेखक - संजय गोस्वामी/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 8067

बाएँ से दाएँ

1.जी,इच्छा,चित्त-2
2.तन,बदन,देह-3
4.अग्निदग्ध-2
6.रनिवास (उर्दू-3)
7.स्नान करना-3
8.विश्राम-3
9.राजा,सम्राट-3
10.वचन,प्रतिज्ञा-3
11.तरंग,हिलोर-3
13.दौड़ना (अंग्रेजी-2)
14.सही का विलोम-3
15.सद्पुरुष-2
16.पाठ,शिक्षा-3
17.कर्ता,कार्य करने वाला-3
18.इज्जत,मान,सम्मान-3
19.सब कुछ छीन लेना-2
20.भवन,प्रासाद-3
21.वजह-3
23.खेल दिखाने वाला-2
24.पेन,लेखनी-3
25.ठाठ-बाट-2

ऊपर से नीचे

1.राय,वोट,अभिप्राय-2
2.लाज,लज्जा-2
3.500 कागजों की गड्डी -2
4.दुनिया,जगत-3
5.लेकर आना-2
6.अवैध,नाजायज-3
7.निगाह,दृष्टि-3
8.बैठने की जगह-3
9.आराम,मदद-3
10.कर्म,भाग्य-3
11.लगन,जिद,उत्साह-3
12.दांपत्य संबंध विच्छेद-3
14.जवान,तरुण-3
15.रिक्त जगह पूर्ण करना-3
16.दुर्बल का विलोम-3
17.वजह-3
18.पदचाप, किसी के आने की आवाज-3
19.रनिवास (उर्दू-3)
20.जी,इच्छा,चित्त-2
21.समयगति-2
22.देह,बदन-2

शब्द पहेली -8066 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

कपिल ने गायकवाड़ की सहायता के लिए बीसीसीआई से अपील की

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ब्लड कैंसर से जझ रहे अपने पुराने साथी बल्लेबाज अंशुमान गायकवाड़ की सहायता के लिए क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से अपील की है। गायकवाड़ का अभी ब्लड कैंसर के लिए लंदन के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गायकवाड़ भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज कोच और चयनकर्ता रहे हैं। कपिल ने कहा कि अपने पुरानी साथी की हालत देखकर हम बेहद दुखी हैं। कपिल ने कहा कि मैं दर्द में हूं क्योंकि मैं अंशुमान के साथ खेला हूं और उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड उनका ध्यान रखेगा। कपिल के अलावा मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, दिलीप वेंगसरकर, मदन लाल, रवि शास्त्री और कीर्ति आज़ाद ने भी गायकवाड़ की सहायता की अपील की है। भावुक कपिल ने कहा कि हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं। ये सहायता आपके दिल से आनी चाह

हिन्दी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो कानून की पढ़ाई-चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

लखनऊ (ईएमएस)। भारत के मुख्य न्यायधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉ की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषा में कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूं कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया में हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और मेरा सोचता हूं कि आरएम एनएलयू को जरूर हिंदी में एलएलबी कोर्स शुरू करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूण शनिवार को राजधानी लखनऊ के डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि डीवाई चंद्रचूड ने इस मौके पर छात्रों को उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अपने सम्बोधन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े कानूनों को भी पढ़ाना जाना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वविद्यालय के पड़ोस के गांव में, गांव से विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की विधिक सहायता केंद्र में आता है और अपनी जमीन से जुड़ी समस्या को बताता है, लेकिन यदि छात्र को खसरा और खतौनी का मतलब ही नहीं पता है तो छात्र उस व्यक्ति को कैसे मदद कर पाएगा। इसलिए जमीन संबंधित क्षेत्रीय कानूनों के बारे में भी छात्र को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ऐसे कई निर्देश दिए हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णय में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37000 निर्णय है, जिनका हिंदी में अनुवाद हो गया है और यह सेवा सब नागरिकों के लिए मुफ्त है।

वहीं, अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पर हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के इस शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आमजन की धारणा बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा बदलने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय एक सही राह पर आगे बढ़ चुका है। यहां के उपाधि प्राप्त करने वाले जितने भी स्नातक, परास्नातक और शोध करने वाले छात्र हैं, वे अपने कार्यों के माध्यम से न सिर्फ विश्वविद्यालय को बल्कि समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करके अपने अभिभावकों और अपने गुरुजनों को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायायल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमरपाल सिंह, विभागाध्यक्ष विधि प्रो. आदित्य प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई न्यायमूर्ति उपस्थित रहे। कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया में हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए आरएम एनएलयू को जरूर हिंदी में एलएलबी कोर्स शुरू करना चाहिए।

आईएएस पूजा के पेरेंट्स समेत 7 पर एफआईआर

मुंबई(ईएमएस)। महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएसअधिकारी पूजा खेडकर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। यह मामला उनकी मां से जुड़ा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धडावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने जमीन खरीदी है। मामले को लेकर शनिवार सुबह पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया एफआईआर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत दर्ज की गई है। साथ ही आम्र्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए हैं।

दिलीप महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। स्थानीय लोगों का दावा था कि खेडकर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और किसानों को धमकाया। किसान कुलदीप पासलकर ने दावा किया कि मनोरमा जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रही हैं।

जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर भारत ने मैच और सीरीज जीती, शुभमन-यशस्वी के अर्धशतक

हरारे (ईएमएस)। भारत ने टी-20 सीरीज के चौथे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा कर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली है। सीरीज का पांचवां मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए टारगेट हासिल कर लिया।

भारत की ओर से ओपनर्स के बीच नाबाद 156 रन की साझेदरी हुई। यशस्वी जायसवाल ने 53 बॉल पर नाबाद 93 और शुभमन गिल ने 39 बॉल पर 58 रन बनाए।

इससे पहले, जिम्बाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। उनके अलावा तदिवनाशे मरुमानी 32 और वेसले मधवरे ने 25 रन का योगदान दिया। जिम्बाब्वे के ओपनर्स तदिवनाशे मरुमानी (32) और वेसले मधवरे (25) के बीच 63 रन की साझेदारी हुई।

भारत की ओर से खलील अहमद ने दो विकेट झटके। शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, तुषार देशपांडे और वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट मिला। जोनाथन कैंपबेल को रवि बिश्नोई ने अपनी ही बॉल पर डायरेक्ट हिट पर रन आउट किया।

अंतिम संस्कार के बाद राखउठाते ही ऐसी चीज हाथ लगी की सब रह गए हैरान

महिला की प्रसव के दौरान हुई थी मौत, पुलिस से की शिकायत, जांच शुरु

मेरठ,(ईएमएस)। डॉक्टर्स को लोग भगवान का दूसरा रुप मानते हैं। भगवान इंसान को जिंदगी देकर दुनिया में भेजता है, तो बीमारियों से डॉक्टर्स इंसान की जान बचाता है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां गंभीर बीमारियों से हार चुके मरीज को डॉक्टर्स नई जिंदगी दी है, लेकिन कई बारे इन्हीं डॉक्टर्स की लापरवाही मरीज की मौत का कारण भी बन जाती है।

मेरठ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इसे नियति मानकर महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। जब चिता जल गई और परिवार वाले उसकी राख जमा करने लगे तब उनके हाथ ऐसी चीज लगी कि सबके होश ही उड़ गए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो शेयर किया गया है।

मामला हस्तिनापुर थाना के राठौरा खुर्द गांव का है। यहां रहने वाले संदीप की पत्नी नवनीत कौर को डिलीवरी के लिए मवाना के जेके अस्पताल में भर्ती करवाया गया था लेकिन सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद परिजन चिता से राख उठा रहे थे, तभी उनके हाथ में एक सर्जिकल ब्लेड आ गई। इसे देखने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में यही सर्जिकल ब्लेड छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।

चिता से ब्लेड निकलते ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। परिजन सीएमओ ऑफिस भी गए। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने घटना सामने आने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही इसके लिए जांच कमेटी गठित की है।

दस इंजीनियरों ने 300 करोड़ रुपए का नहीं दिया हिसाब, अब कसेगा शिकंजा

पटना,(ईएमएस)। बिहार में इस समय बाढ़ से लोग परेशान है और प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी में लगा है इसी बीच नीतीश सरकार पुराने हिसाब-किताब में उलझी हुई है। पिछले साल बाढ़ में राहत और बचाव के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे, लेकिन कई इंजीनियर और अधिकारी उसका हिसाब आज तक नहीं दे पाए। अब सरकार इन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

जानकारी के मुताबिक पिछले साल बाढ़ में जल संसाधन विभाग के दस इंजीनियरों को राहत और बचाव के लिए करीब 300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इन इंजीनियरों ने अब तक इसका हिसाब नहीं दिया है। इनमें छह सहायक इंजीनियर और चार कनीय इंजीनियर शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए यह पैसा अग्रिम रूप से दिया गया था, लेकिन इसका हिसाब अभी तक नहीं मिला है। कई बार कहने पर भी जब इंजीनियरों ने हिसाब नहीं दिया तो अब कार्यपालक अभियंता ने इन इंजीनियरों को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द रुपए जमा कराएं नहीं तो उन पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसा कनीय इंजीनियरों के पास है। इसमें से अकेले सकलदेव सिंह जूनियर इंजीनियर के पास 142 करोड़ रुपए हैं। यह पैसा उन्हें पिछले साल पुनपुन नदी में बाढ़ राहत कार्यों के लिए दिया गया था। नियम के मुताबिक इंजीनियरों को काम खत्म होने के बाद बचा हुआ रुपया वापस सरकारी खजाने में जमा कराना था। हैरानी की बात है यह कि अभी तक उन्होंने रुपया जमा नहीं कराया है। अब एक बार फिर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो सरकार इन इंजीनियरों से हिसाब लेने की तैयारी कर रही है।

17 कंपनियों ने खरीदे प्लॉट अब यमुना अथॉरिटी करेगी निरस्त

इन प्लॉट पर न तो निर्माण किया और न ही नक्शा कराया पास

ग्रेटर नोएडा,(ईएमएस)। यमुना अथॉरिटी एरिया स्थित स्पेशल डिवेलपमेंट जोन परियोजना के तहत जेपी ग्रुप की ओर से 17 कंपनियों को सब-लीज किए गए ग्रुप हाउसिंग प्लॉट को यमुना अथॉरिटी अब निरस्त कर रही है। इसके लिए अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। अथॉरिटी का कहना है कि 2009 में इस परियोजना के लिए जेपी ग्रुप को जमीन दी थी लेकिन 14 साल बाद भी जेपी की इन 17 सबलेसी कंपनियों ने इन प्लॉट पर न तो निर्माण किया और न ही नक्शा पास कराया। अब अथॉरिटी इन्हें निरस्त करने की कार्रवाई करने जा रही है।

यमुना अथॉरिटी के सेक्टर-25 में जेपी असोसिएट्स को एसडीजेड परियोजना के तहत एक हजार हेक्टेयर जमीन का आवंटन 2009 में किया था। इसमें करीब 600 एकड़ जमीन पर 32 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट आने थे। इनमें से 11 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट जेपी को खुद बनाने थे। इनमें से कुछ पर काम चल रहा और कुछ फंसे हैं। बाकी के 19 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट के प्लॉट बिल्डर ने दूसरी कंपनियों को सब-लीज कर दिए।

सब-लीज होने वाली कंपनियों में बैंक भी थे। लैंडयूज के हिसाब से इन पर ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट ही डिवेलप किया जा सकता था चाहे उसे कोई भी बनाए। इन 19 में से 17 ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों की सबलेसी कंपनियों ने 14 साल में न तो इन पर कोई निर्माण किया है, न ही कोई नक्शा पास कराया और न ही इनके बारे में किसी दूसरे को बेचे जाने की कोई सूचना अथॉरिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है।

गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेसवे स्थित बुद्ध इंटरनैशनल सर्किट भी एसडीजेड परियोजना का हिस्सा है। इसे बिल्डर ने खुद बनाया था जिस जमीन पर यह बना है उसका पैसा जेपी असोसिएट्स ने अथॉरिटी को नहीं चुकाया। इसके चलते इस प्लॉट को भी अथॉरिटी ने निरस्त दिया है। इसे बहाल कराने के लिए अथॉरिटी और बिल्डर के बीच कोर्ट में मामला चल रहा है।

यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एसडीजेड परियोजना में बिल्डर को एक हजार हेक्टेयर जमीन अथॉरिटी ने 2009 में आवंटित की थी। इसमें 17 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की बिल्डर ने दूसरी कंपनियों को सब-लीज यानी बेच दिया। इस योजना के तहत एक तय समय में इन प्लॉट पर निर्माण होना था। अब वह डेडलाइन निकल चुकी है लेकिन अभी तक नक्शा भी पास नहीं हुआ है। इसके चलते अब इन्हें निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। जवाब के लिए सप्ताह भर का नोटिस दिया गया है।

फ्लाइट में नशे में धुत शख्स ने पेशाब किया

शिकागो(ईएमएस)। नशे में धुत एक यात्री ने बुधवार को अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिग करने के लिए मजबूर कर दिया। यात्री ने फ्लाइट में यात्रियों के सामने अपने कपड़े उतार दिए और गलियारे में ही पेशाब कर दी थी। नील मैक्कार्थी (25) नाम के इस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। उस पर पब्लिक में अभद्र प्रदर्शन करने के आरोप लगाए गए हैं। ओरेगन के रहने वाले मैक्कार्थी ने माना है कि उसने व्हिस्की की कई बोतलें पी रखी थीं। ये घटना अमेरिकन ईगल फ्लाइट 3921 में हुई। विमान शिकागो से मैनचेस्टर जा रही थी। नील मैक्कार्थी के पेशाब कर देने के कारण विमान की बफैलो, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

अब महाराष्ट्र सरकार कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक बेचने पर लगाएगी बैन

स्कूल, कॉलेज के आसपास बेचा तो होगी सख्त कार्रवाई

मुंबई,(ईएमएस)। अब महाराष्ट्र सरकार स्कूल और कॉलेज के पास कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षण के बाद ऐसे ड्रिंक बेचने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में यह घोषणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने की। मंत्री आत्राम ने कहा कि एनर्जी ड्रिंक के विज्ञापनों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस विधायक सत्यजीत तांबे ने विधान परिषद में बच्चों और छात्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने नशा मुक्त महाराष्ट्र अभियान शुरू किया है लेकिन राज्य में किराना दुकान, मॉल और स्कूल, कॉलेज के आसपास की दुकानों में कम कीमत पर कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक ख़ुलेआम बेचा जा रहा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए यह नशे की तरह हैं। मुंबई सहित राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक छात्रों के स्वास्थ्य के लिए ख़तरा बन गए हैं। इसे गंभीर मामला मानते हुए सभापति नीलम गोर्हे ने चिंता जताई और संबंधित मंत्री और प्रशासन को 15 दिनों में बैठक करने का आदेश दिया।

कांग्रेस विधायक तांबे ने कहा कि विज्ञापनों के बाद युवाओं में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कैफीन युक्त कोल्ड ड्रिंक का सेवन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। ये ड्रिंक सेहत के लिए बड़ा खतरा है। स्कूल परिसर में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री से यह स्कूली बच्चों तक आसानी से पहुंच रहा है। राज्य में स्कूल परिसरों में कैफीन युक्त कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने स्कूल परिसर के 500 मीटर के दायरे में कैफीन युक्त पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी।

उत्तराखंड में बाढ़ से पिथौरागढ़-तवाघाट मार्ग बंद

देहरादून,(ईएमएस)। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी है। पिथौरागढ़ में धारचूला से करीब 14 किलोमीटर दूर बाढ़ से कुलागाढ़ में भारी मलबा जमा हो गया है। मलबे के कारण काली नदी का प्रवाह भी तेज हो गया है। बाढ़ से नदी उफान पर है, जिसके चलते पिथौरागढ़-तवाघाट मार्ग बंद है। टनकपुर-पिथौरागढ़ हाईवे पर बने पुल के टूटने की खबर भी सामने आई थी लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल सुरक्षित है। पुल के आसपास भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ है।

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित धारचूला में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहां कुलागाढ़ नाले में नदी के पास झील बन गई है, जिससे पुल को खतरा उत्पन्न हो गया है। पिथौरागढ़ जिला आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक कल धारचूला क्षेत्र में बाढ़ से आठ किलोमीटर दूर बहने वाला कुलागाढ़ नाला उफन गया है।

बीएसएनएल कर सकता है एमटीएनएल का संचालन

नई दिल्ली,(ईएमएस)। केंद्र सरकार एक समझौते के तहत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का संचालन बीएसएनएल को सौंपे जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों की मानें तो सरकार एमटीएनएल का विलय करने की बजाय इस विकल्प पर विचार कर रही है। विलय या संचालन पर अंतिम फैसला महीनेभर में लिए जाने की संभावना व्यक्त की गई है।

सूत्रों का कहना है कि कर्ज में बुरी तरह डूब चुकी एमटीएनएल का संचालन एक समझौते के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपे जाने के विकल्प पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि एमटीएनएल भारी कर्ज में डूबी है, ऐसे में बीएसएनएल के साथ विलय अनुकूल विकल्प नहीं होगा। इस मामले में फैसला ले लिए जाने के बाद प्रस्ताव सचिवों की समिति के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय करेगा।

गौरतलब है कि एमटीएनएल ने बढ़ते वित्तीय संकट के चलते इस सप्ताह शेयर बाजार को सूचना दी थी कि वह अपर्याप्त फंड के कारण कुछ बॉन्डधारकों को ब्याज का भुगतान करने में खुद को असमर्थ पा रही है। यह ब्याज रकम 20 जुलाई 2024 को देय है। एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग और बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के मुताबिक एमटीएनएल को भुगतान तारीख से 10 दिन पहले एस्क्रो खाते में पर्याप्त राशि के साथ अर्धवार्षिक ब्याज राशि जमा करनी होगी। इसके तहत ही एमटीएनएल ने सूचित किया है कि एमटीएनएल एस्क्रो खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं कर सकी है। यहां बताते चलें कि एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं देती हैं, जबकि बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़ कर संपूर्ण देश में परिचालन करती है।

इस्राइल ने गाजा में बरपाया कहर, 71 की मौत

येरुशलम (ईएमएस)। बीते नौ महीने से इस्राइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इस्राइल ने हमास को खत्म करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली है। यह प्रतिज्ञा गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रही है। गाजा में इस्राइली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच खबर आई है कि इस्राइल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर भीषण हमला किया है। इस हमले में हमास की सैन्य टुकड़ी के प्रमुख मोहम्मद दईफ समेत 71 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी है।

उधर, इस्राइली अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हमास की सैन्य टुकड़ी के प्रमुख मोहम्मद दईफ पर निशाना साधा था। इस्राइल ने गाजा पट्टी के खान यूनिस क्षेत्र में यह हमला किया है। इस्राइली अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दईफ के ठिकानों पर हवाई हमला किया। मोहम्मद दईफ को इस्राइल में सात अक्तूबर 2023 में हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। आपको बता दें कि इस्राइल में सात अक्तूबर को हमास ने कहर बरपाया था। उस दौरान 1,200 लोग मारे गए थे। इस वजह इस्राइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई थी।

प्रचंड नहीं हासिल कर सके विश्वासमत, ओली ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

काठमांडू,(ईएमएस)। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दाहाल प्रचंड संसद में विश्वासमत हासिल नहीं कर सके। उसके बाद पूर्व पीएम के पी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। पिछले सप्ताह सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) ने अपना समर्थन वापस ले लिया था।

इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पूर्व पीएम के.पी. ओली के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष 165 सांसदों के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इन सांसदों में उनकी पार्टी के 77 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद हैं।

इससे पहले 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में मतविभाजन के दौरान प्रचंड को 63 वोट मिले, जबकि विश्वासमत प्रस्ताव के विरोध में 194 वोट पड़े। प्रचंड को विश्वासमत हासिल करने के लिए कम से कम 138 वोट की जरूरत थी। प्रतिनिधि सभा के 258 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया, जबकि एक सदस्य मतदान में शामिल नहीं हुआ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओइस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी) के अध्यक्ष प्रचंड 25 दिसंबर, 2022 को पद संभालने के बाद चार बार विश्वासमत हासिल करने में सफल रहे हैं लेकिन इस बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा है। इससे नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के लिए नई गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व पीएम के.पी. ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल ने सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता-साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पिछले सप्ताह प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा पहले ही अगले पीएम के रूप में ओली का समर्थन कर चुके हैं। देउबा और ओली ने प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को अपदस्थ करने और नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सात सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक ओली और देउबा बारी-बारी से पीएम पद साझा करेंगे। पहले चरण में ओली डेढ़ साल पीएम बनेंगे और उसके बाद बची हुई अवधि में देउबा पीएम बनेंगे।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.16 अरब डॉलर बढ़ा

मुंबई (ईएमएस)। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच जुलाई को समाप्त सप्ताह में 5.16 अरब डॉलर उछलकर 657.16 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार 1.71 अरब डॉलर घटकर 651.99 अरब डॉलर रहा था। इस वर्ष सात जून को विदेशी मुद्रा भंडार 655.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पांच जुलाई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.23 अरब डॉलर बढ़कर 577.11 अरब डॉलर हो गयी। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 90.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 57.43 अरब डॉलर रहा। विशेष आहरण अधिकार (एसडी आर) 2.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.04 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 40 लाख डॉलर बढ़कर 4.58 अरब डॉलर हो गई।

सब्जियों और फलों के भाव आसमान पर, लहसुन 300 रुपए किलो

नई दिल्ली (ईएमएस)। बरसात और बदलते मौसम के कारण सब्जी व फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, ?जिसकी वजह से लोगों को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार सिरसा में प्याज के दाम?60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि लहसुन की कीमत 300 रुपये किलो से अधिक है। इसके अलावा हरी सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। दरअसल, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि दाम बढ़ जाने के कारण खरीददारी में कमी आई है। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो तो अगले कुछ और दिनों तक सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। सिरसा की सब्जी मंडी में इस समय प्याज 60 से 70 रुपये किलो, टमाटर 70 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो, लहसुन 300 रुपये किलो, खीरा 60 रुपये किलो, अरबी 80 रुपये किलो, नींबू 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। सब्जियों और फल के दामों में आए उछाल के कारण आम जनता को अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ रही है। सिरसा की सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों का मानना है कि पहले के मुकाबले रोजाना अब सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से वह पहले के मुकाबले अब कम ही सब्जियां और फल खरीद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक सब्जी और फल के लिए दोगुना रेट देना पड़ रहा है।

निजी कंपनियों के टैरिफ बढ़ने से फिर चमकी बीएसएनएल की किस्मत

- लाखों लोग अपनी सिम को बी.एस.एन.एल. में करवा रहे हैं पोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में एक समय था जबजब भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का सिम लेने के ?लिए लंबी कतारें लगा करतीं थी, उसके बाद ?निजी कंप?नियों के बाजार में आने से बी.एस.एन.एल. इनके आगे बौना साबित हो गया और इस ग्राहकों ने अपने मोबाइल नंबर निजी टेलीकॉम ऑपरेटर को पोर्ट करा दिए। दरअसल सरकार की नीतियों के चलते यह निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाया। अलबत्ता अब बी.एस.एन.एल. के पास कमाई का एक और मौका हाथ लगा है जब देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां, जियो, एयरटेल और वी.आई. (वोडाफोन), ने इसी महीने से अपने बढ़े हुए टैरिफ लागू कर दिए। टैरिफ में बढ़ोतरी इतनी ज्यादा है कि लाखों लोग सस्ते प्लान के लिए अपने सिम बी.एस.एन.एल. में पोर्ट करवा रहे हैं। जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम 3 जुलाई से लागू हो गए, जबकि वी.आई. के दाम 4 जुलाई से लागू हुए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जियो ने की है, जिसने अपने प्लान के दाम 12 से 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। एयरटेल ने 11 से 21 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, जबकि वी.आई. ने 10 से 21 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए हैं। इस वृद्धि से सबसे ज्यादा नाराजगी जियो को लेकर है, जिसके कारण लोग अब बी.एस.एन.एल. की तरफ रुख कर रहे हैं। बी.एस.एन.एल. नए प्लान पेश करके और अपने मौजूदा प्लान में अतिरिक्त लाभ देकर इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी अगले महीने देश भर में अपनी 4 जी सेवाएं भी लॉन्च कर सकती है। बी.एस.एन.एल. के पास उपयोगकर्ताओं के लिए कई किफायती प्लान्स पहले से मौजूद हैं। अगर कम पैसों में लंबी वैधता वाला रिचार्ज करवाना है, तो 397 रुपये वाला प्लान सही रहेगा। इसमें 150 दिन की वैधता मिलेगी।

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद की तो चीन को भुगतने होंगे परिणाम

-अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर चीन को चेताया

वाशिंगटन,(ईएमएस)। चीन अक्सर अपनी गतिविधियों के चलते खबरों में बना रहता है और अपने आसपास के देशों पर धाक जमाने की कोशिश करता रहता है लेकिन चीन का कट्टर दुश्मन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर चीन के खिलाफ आवाज उठाई है। बाइडन ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के लिए चीन को परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश पूर्वी एशियाई देश में अपने निवेश को कम करने जा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडन ने कहा कि मुद्दा यह है कि हमें यह तय करना होगा कि शी जिनपिंग यह समझें कि प्रशांत बेसिन के साथ-साथ यूरोप और रूस से संबंधित और यूक्रेन से निपटने के लिए कीमत चुकानी होगी। यदि आप चीन में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास 51 फीसदी चीनी मालिक होना चाहिए। आपको यह तय करना होगा कि आप उनके नियमों का पालन करें और अपने पास मौजूद डेटा और सूचनाओं तक सभी पहुंच प्रदान करें।

बाइडन ने कहा वे सरकारी वित्तपोषण द्वारा उत्पादों को रियायत देने संबंधी अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करते तो इस प्रकार वे बिना किसी महत्वपूर्ण शुल्क के अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को अमेरिका में निर्यात करने में सक्षम नहीं होंगे। अन्य देश भी दुनिया भर में यही कर रहे हैं, लेकिन यह चिंता का विषय है। चीन, उत्तर कोरिया, रूस, ईरान जैसे देशों में हो सकता है कि अतीत में समन्वय नहीं रह

अहमदाबाद में आयोजित 'गुजरात गुणवत्ता संकल्प' कार्यक्रम का शुभारंभ

कानून -व्यवस्था में गुणवत्ता होगी तो ही गुणवत्ता का जीवन संभव

अहमदाबाद, १३ जुलाई ।

अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 'गुजरात गुणवत्ता संकल्प' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 'गुणवत्ता रोडमैप' विषय पर आयोजित सत्र में गृहराज्य मंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे। अहमदाबाद में आयोजित समारोह में गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार दास से चर्चा करते हुए।

अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 'गुजरात गुणवत्ता संकल्प' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 'गुणवत्ताशोडमैप' विषय पर आयोजित सत्र में गृहराज्य मंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे। उन्होंने इस विषय पर संवाद करते कहा कि गुणवत्ता का जीवन तभी संभव है जब कानून और व्यवस्था में गुणवत्ता होगी।

संघवी ने कानून और व्यवस्था के बारे में कहा कि, गुणवत्ता का जीवन तभी संभव है जब कानून और व्यवस्था में गुणवत्ता हो। शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मामले में गुजरात पूरे देश में अग्रणी राज्य है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर कहा कि, राज्य में पिछले ८ दिनों में पोक्सो रेप जैसे मामलों के आरोपियों के खिलाफ पांच से आठ दिनों में आरोपपत्र दाखिल कर पीड़ितों को न्याय दिलाया गया है। ड्रग्स के दूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि, ड्रग्स पकड़ने के मामले में गुजरात पूरे देश में सबसे आगे है।

इस सत्र में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव एम.के.दास ने कहा कि भारत हमेशा से गुणवत्ता से भरपूर देश रहा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि भारत कई क्षेत्रों में अग्रणी है। गुणवत्ता के बारे में उन्होंने सभी से कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हर क्षेत्र में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही हमें अपनी निष्ठा और वचनबद्धता पर भी कायम रहना होगा।

सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रधान सचिव मोना खंधार ने स्वास्थ्य अवसंरचना के बारे में बात की। उन्होंने अपने विभाग कार्यों में गुणवत्ता के बारे में ध्यान रखने पर भी बात की। इसके अलावा, उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के बारे में भी विस्तृत चर्चा की। इस सत्र में 'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया' के चेयरपर्सन श्री जक्षय शाह, सचिव श्री चक्रवर्ती कन्नन सहित कई लोग उपस्थित थे।

विदेश में बसने की चाहत पड़ी महंगी, चार दोस्तों ने गंवाए 1.60 करोड़

अहमदाबाद (ईएमएस) किसी भी कीमत पर विदेश जाने की चाहत रखने वाले खासकर युवाओं को सतर्क करने वाली घटना सामने आई है। विदेश में बसने की लालसा में अहमदाबाद के 4 दोस्तों ने रु. 1.60 करोड़ गंवा दिए। पीड़ित युवक की शिकायत पर सीआईडी क्राइम ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के न्यू राणिप की शिव दर्शन सोसायटी निवासी 38 वर्षीय हार्दिक पटेल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वर्ष 2021 में हार्दिक पटेल समेत उनके तीन दोस्तों ने कनाडा में पीआई विजा प्राप्त कर वहीं स्थायी होने का फैसला किया। जिसके बाद गूगल पर सर्च कर वडोदरा की विजा कन्सल्टन्सी से संपर्क किया। ऋषिकेश पुरोहित नामक एजन्ट ने कनाडा के विजा के लिए प्रति व्यक्ति रु. 40 लाख की मांग की। विदेश जाने का सपना देख रहे चारों दोस्तों ने वर्ष 2021 से 2023 के दौरान किश्तों में रु. 1.60 करोड़ ऋषिकेश पुरोहित को दे दिए। रुपए मिलनेके बाद कनाडा का वर्क परमिट और पीआई विजा दिलाने की लालच देनेवाले ऋषिकेश पुरोहित और उसके साथियों ने अहमदाबाद के हार्दिक पटेल समेत उसके दोस्तों को बताया कि विजा रिजेक्ट हो गया है और कनाडा के बजाए किसी और राज्य के विजा के लिए अप्लाई करने होगा। बाद में ऋषिकेश पुरोहित ऑफिस बंद कर फरार हो गया। रुपए देने के बाद भी जब विजा नहीं मिला तो हार्दिक पटेल ने सीआईडी क्राइम में वडोदरा के ऋषिकेश पुरोहित, देहरादून के विश्वदीप बिनोद और मणिनगर की सुजाता वाधवा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवा दी। जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि फर्जी मार्कसीट बनाने के मामले में ऋषिकेश पुरोहित को वडोदरा क्राइम ब्रांच द्वारा पहले गिरफ्तार किया गया था।

BJP विधायक का इस्तीफा नहीं तो परिवार समेत अपना लूंगा इस्लाम, गुजरात में दलित कांग्रेस नेता राजेश सोलंकी की धमकी

अहमदाबाद : कांग्रेस के जूनागढ़ शहर एससी/एसटी सेल के अध्यक्ष राजेश सोलंकी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम कबूल कर लेंगे। राजेश सोलंकी के बेटे पर मई में बीजेपी विधायक गीताबा जडेजा के बेटे ने कथित रूप से हमला किया था। राजेश ने कहा कि अगर गुजरात की बीजेपी सरकार विधायक का इस्तीफा और उनके पति की गिरफ्तारी की मांग नहीं मानती तो वह शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वह दलित समुदाय से आते हैं लेकिन उनका पूरा परिवार और उनके कुछ अन्य लोग इस्लाम में परिवर्तित हो जाएंगे।

गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने इन दिनों राज्य में सनसनी मचा दी है। कांग्रेस लीडर राजेश सोलंकी जूनागढ़ शहर एससी/एसटी इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने गोंडाल से भाजपा विधायक गीताबा जडेजा के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक के पति को भी गिरफ्तार किया जाए, ऐसा नहीं हुआ तो वह मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। कांग्रेस के जूनागढ़ शहर एससी/एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश सोलंकी दलित समुदाय के अनौपचारिक संगठन जूनागढ़ जिला अनुसुचित जाति समाज के प्रमुख भी हैं। उनके बेटे संजय सोलंकी कांग्रेस की छात्र शाखा-भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के नेता हैं।

गोंडाल के भाजपा विधायक गीताबा जडेजा के बेटे ज्योतिरा दित्या सिंह उर्फ गणेश को संजय पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को राजेश सोलंकी जूनागढ़ के जिला कलेक्टर के कार्यालय गए और राज्य सरकार से धर्म परिवर्तन की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र एकत्र किए।

पाटण में बस और ट्रक हादसे में ४ की मौत, बस में सवार ६ यात्री घायल हो गए

पाटण, १३ जुलाई ।

शधनपुर के खारिया पुल के पास आणंद से शपर जा रही एसटी बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ४ लोगों की मौत हो गई है। जिसमें बस के ड्राइवर और कंडक्टर और ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर शामिल हैं। जबकि बस में सवार ६ यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को शधनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आधी रात हुई घटना से हाईवे पर मौत की चीख-पुकार मच गई।

मिली जानकारी के अनुसार शधनपुर में खारिया नदी पुल के पास रपरिया हनुमान से आगे सड़क पर दोपहर करीब दो बजे आणंद से शपर जा रही एसटी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। बस और ट्रक दोनों के ड्राइवर समेत एसटी और ट्रक के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। साथ ही दोनों वाहनों को अलग करने के लिए क्रेन की मदद ली गई। हादसे की जानकारी जब पुलिस और एसटी विभाग के अधिकारियों को हुई तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अमरजीवन समर्पण की एंबुलेंस वैन से पाटण और मेहसाणा भेजा गया है।

मृतकों में ठाकोर कनुजी शंकर, (४१) बस चालक, वडनगर, जिला मेहसाणा निवासी, ठाकोर लालाभाई वाहजी भाई (३३) अमीरपुरा, शधनपुर निवासी, बजनिया अमरतभाई रैमसे भाई (३०) ट्रक ड्राइवर, जरुरा, जिला सांतलपुर निवासी, ठाकोर निकुलभाई भारू भाई (२०) बमरोली, सांतलपुर निवासी शामिल है, जबकि ६ यात्री घायल हो गए है। इन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, हादसे से दोनों हाईवे पर जाम लग गया। जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क को यातायात के लिए खुलवाया। शधनपुर के पीआईबीएम चौधरी ने बताया कि दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन एसटी बस और ट्रक के ड्राइवर समेत कुल ४ लोगों की मौत हो गई है।

फिलहाल पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। जबकि घायलों का इलाज पाटण और महेसाणा में हो रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को शधनपुर के अलावा मेहसाणा के सतलासाणा में भी एक हादसा हुआ है। जिसमें धरोई बांध से वडाली रोड पर दो इको गाड़ियां आमने-सामने टकरा गईं। जिससे ईको में सवार ८ लोग घायल हो गए है। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए वडनगर के १०८ सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनंत-राधिका की शादी में किंजल दवे ने पहना लाखों रुपये का आउटफिट

वडोदरा, १३ जुलाई ।

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट १२ जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए। शादी से पहले परिवार ने कई तरह के जश्न मनाए जिसमें गरबा नाइट भी शामिल था। डांडिया नाइट मनाते हुए यह जोड़ा एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। बता दें कि गुजरात की गरबा क्वीन किंजल दवे के गाने पर पूरे अंबानी परिवार समेत तमाम सेलेब्स झूमे थे।

देश के मशहूर और सबसे अमीर अंबानी परिवार के आंगन में शुभ अवसर आयोजित किया गया था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट १२ जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए, जिसमें देश-विदेश की मशहूर हस्तियां जुटीं। इस शादी से पहले गरबा का आयोजन किया गया था जिसमें गुजरात की गरबा क्वीन किंजल दवे के गाने पर पूरे अंबानी परिवार समेत तमाम सेलेब्स झूमे थे।

इस परफॉर्मेंस में किंजल दवे ने चंदेरी सिल्क से बनी आउटफिट पहना था जीसने सबका ध्यान खींचा। अंबानी परिवार के गरबा में परफॉर्म करने वाली किंजल दवे का आउटफिट डिजाइन और तैयार करने वाले फैशन डिजाइनर अन्नू पटेल से गुजराती जागरण ने खास बातचीत की जिसे हम यहां पेश कर रहे हैं।

फैशन डिजाइनर अन्नू पटेल ने आगे कहा कि किंजल दवे के आउटफिट को बनाने में १६ कारीगरों को २२ दिन लगे। इसमे चनिये का घेराव ८ से ९ मीटर का है और इस पर विंटेज वर्क किया गया है। इस आउटफिट की कीमत १,९०,००० रुपये है। इस आउटफिट की सबसे खास बात ये है कि ये दोबारा इस आउटफिट की कॉपी नहीं हो सकती, अगर कोई इसे दूसरी बार भी बनाएगा तो ये सिमिलर ही हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता।

किंजल दवे ने अन्नू पटेल द्वारा डिजाइन किए गए आउटफिट में वीडियो शेयर किया और लिखा, 'मेरी जिंदगी के हर खास पल को खास बनाने के लिए @annu patel को धन्यवाद। मेरे पोशाक को इतने प्यार से बनाने और हमेशा मुझे कुछ खास और नया देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद; आपने मेरे लिए जो भी डिजाइन तैयार किए हैं, वे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप मेरे सभी अनमोल पलों का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। मेरे सभी लुक्स पर इतनी मेहनत करने के लिए अन्नु पटेल को बहुत-बहुत धन्यवाद।'

डॉक्टर और स्टाफ हुए फरार, मरीजों में दहशत

अहमदाबाद, १३ जुलाई ।

राज्य में फर्जी स्कूल पकड़े जाने के बाद अहमदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में फर्जी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल का भी भंडाफोड़ हुआ है। जिला प्रशासन की टीम ने इसे सील किया। फर्जी डॉक्टर मेहुल चावड़ा इस अस्पताल का संचालन कर रहा था। हॉस्पिटल सील होने के बाद अब डॉक्टर अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ मौके से फरार है।

गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। हमने फर्जी डॉक्टरों को छोटे-मोटे जनरल क्लीनिक चलाते देखा है, लेकिन यहां ग्रामीण इलाकों में एक फर्जी डॉक्टर पूरा मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल चला रहा था। यह डॉक्टर दो फर्जी अस्पताल चला रहा था। यह अब तक इलाज के नाम पर मरीजों से लाखों रुपए वसूल उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा था। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने फर्जी डॉक्टर के दोनों हॉस्पिटल को सील कर दिया।

यह कार्रवाई सानंद के मोरैया में की गई है। यहां मोरैया जनरल हॉस्पिटल के नाम से मेहूल चावडा नाम का फर्जी डॉक्टर अस्पताल चला रहा था। फिलहाल आरोपी अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ फरार है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुटी है।

अहमदाबाद जिले के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक मोरैया जनरल हॉस्पिटल पर छापा मारा। मगर छापेमारी से पहले ही फर्जी डॉक्टर मेहुल चावड़ा अस्पताल के उपकरण व स्टाफ के साथ फरार हो गया था। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक वायरल वीडियो मिला, जो मृत बच्ची के परिवार ने अपलोड किया था। इसके मुताबिक, बेटी को किसी बीमारी के चलते सुबह बावला स्थित अनन्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और रात में उसकी मौत हो गई। इस वीडियो में परिवार कह रहा है कि सुबह बेटी ठीक थी। डॉक्टर से बार-बार रिपोर्ट मांगने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दी। अस्पताल ने १.५० लाख रुपए इलाज शुल्क लिया।

पिछले दिनों ही उन्होंने डॉ. मेहुल चावडा के ही संचालन में चल रहे अनन्या हॉस्पिटल को सील किया था। एक वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के लिए वीडियो की जांच की। जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीडीएचओ डॉ. शैलेश परमार के नेतृत्व में बावला स्थित अनन्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पर पुलिस के साथ छापा मारा था। यह छापा १० जुलाई को मारा गया था। जिसमें बात सामने आई थी की एक शख्स बिना किसी डिग्री के डॉक्टर बनकर मरीजों की जान खतरे में डाल रहा है।

पिछले दिनों राजकोट जिला प्रशासन ने गौरी प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से चल फर्जी स्कूल को सील किया था। यहां अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जा रहा था। बीते साल भी गुजरात में एक फर्जी टोल नाका पकड़ा गया था। उसके बाद एक फर्जी सरकारी कार्यालय चलने का मामला भी सामने आया था।

दिवाली पर गांव जाने की जद्दोजहद हुई शुरू:भीड़ ऐसी कि रेगुलर ट्रेनें अभी से रिग्रेट

सूरत, १३ जुलाई ।

दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर उत्तर और पूर्वी भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनें अभी से रिग्रेट हो गई हैं। चार महीने पहले की एडवांस बुकिंग खुलने के एक हफ्ते के भीतर लगभग सभी रेगुलर ट्रेनें वेटिंग २०० से ४०० तक पहुंचने के बाद रिग्रेट हो गई हैं। भीड़ का आलम यह है कि डायनैमिक फेयर वाली १२९५१ तेजस राजधानी और १२९५३ अगस्त क्रांति राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी वेटिंग चल रही है।

बता दें कि ३१ अक्टूबर २०२४ को दिवाली का त्योहार है। ऐसे में दिवाली की छुट्टी पर हर बार की तरह बड़ी संख्या में लोग बाहर घूमने जाएंगे। हालांकि इस बार दिवाली से लगभग चार महीने पहले ट्रेनों की तस्वीर अलग है। भीड़ इस कदर है कि रेगुलर ट्रेनों में अब दिवाली और छठ के लिए कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है।

सूरत से यूपी-बिहार की ट्रेनों की हालत अभी से खस्ता है। तामी गंगा ट्रेन की बात करें तो दिवाली वीकेंड पर छठ के लिए यह ट्रेन रिग्रेट हो गई है। यानी अब इसमें वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह उधना-दानापुर एक्सप्रेस में वेटिंग ४०० के पार जाने के बाद ट्रेन रिग्रेट हो गई। ऐसे में दिवाली का सफर बहुत मुश्किलों भरा होगा।

पश्चिम रेल के एक अधिकारी ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर हम महीने भर पहले स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करेंगे। इसके अलावा पिछली बार की तरह भीड़ को समायोजित करने के लिए लगातार अनारक्षित ट्रेनें चलाई जाएंगी। क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी की जाएगी। भीड़ वाले रूट चिन्हित कर उस पर स्पेशल, जनरल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पिछली बार दिवाली और इस साल गर्मी की छुट्टियों में क्राउड मैनेजमेंट का प्रयोग किया, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली थी।

२०९३३ उधना-दानापुर एक्सप्रेस दिवाली वीकेंड से ही पैक्ड हो गई है। २ नवंबर के लिए इसकी वेटिंग ४०० के पार पहुंच गई तो यात्रियों ने टिकट रद्द भी कर दिया, लेकिन कैंसिलेशन चार्ज ६०-६० रुपए कट गए। यात्री एसके कुमार ने बताया कि उधना-दानापुर ट्रेन में २ नवंबर को चार टिकट निकाले, लेकिन वेटिंग ४०० के पार होने के बाद ट्रेन रिग्रेट हो गई। कुछ देर बाद टिकट रद्द किए तो प्रति टिकट के ६० रुपए चार्ज कट गए।

दिवाली पर एक तरफ जहां ट्रेनें पैक्ड हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ दिवाली वीकेंड पर यानी २८ अक्टूबर से फ्लाइट का किराया भी आसमान छूने वाला है। दिवाली वीकेंड पर सूरत से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया, इंडिगो की फ्लाइट का किराया अभी से ५००० से ७००० रुपए के पार जा पहुंचा है।

सितंबर तक इनका डायनैमिक फेयर केवल दिल्ली रूट पर १० हजार के पार पहुंचेगा। वहीं सूरत से हैदराबाद फ्लाइट का किराया ४ हजार के पार अभी से है, जबकि बेंगलुरू के लिए सीधी उड़ान का डायनैमिक फेयर अभी से ५ हजार रुपए के पार जा पहुंचा है।

सूरत की लेब में बने हीरे पर उकेरी पीएम मोदी की अनमोल छवि, जानें इसकी खासियतें

अहमदाबाद/सूरतः सूरत के एक हीरा उद्योगपति ने लैब में बने डायमंड पर पीएम मोदी की छवि बनाई है। इसे मोदी डायमंड नाम दिया गया है। लैबग्रोन इस मोदी डायमंड को मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है। पीएम मोदी के तस्वीर वाले डायमंड को बनाने के लिए करीब एक महीने का समय लगा है। मोदी डायमंड आठ कैरेट के डायमंड पर बनाया गया है। सूरत के 25 हीरा कारीगरों ने मिलकर एक महीने में मोदी डायमंड को बनाया है। पीएम मोदी ने सूरत के हीरा व्यापार को ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए हमेशा लेबग्रोन डायमंड के उत्पादन को प्रोत्साहित करते रहे हैं। पिछली बार जब वह सूरत डायमंड बोर्स के शुभारंभ को पहुंचे थे। तब भी उन्होंने यह सपना देखा था कि लेबग्रोन डायमंड में भारत और खासकर सूरत की हिस्सेदारी बढ़े। पीएम मोदी पिछले साल जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने लैब में बनाया गया एक इको फ्रेंडली डायमंड जिल बाइडेन को गिफ्ट किया था। वो डायमंड 7.5 कैरेट का था।

लैब में तैयार किए गए मोदी डायमंड को एक प्रदर्शनी में रखा गया था। जब इसकी सूचना गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को हुई तो वह भी इस मोदी डायमंड का दीदार करने के लिए प्रदर्शन में पहुंचे। इसी साल की शुरुआत में बीजेपी के सूरत के बड़े हीरा कारोबारी गोविंद भाई धोलकिया को राज्यसभा भेजा था। प्रदर्शनी में रखे गए इस डायमंड की क झलक के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि हीरे में पीएम मोदी को छवि वाले इस डायमंड को बाद में नीलाम भी किया जा सकता है। अब देखना यह है कि यह हीरा कितनी कीमत में बिकता है? गुजरात की हीरा नगरी सूरत में एक उद्योगपति में लैब में तैयार किए गए हीरे पर पीएम मोदी की छवि उकेरी है। प्रदर्शनी में रखे गए यह हीरा चर्चा में आ गया है। मां हीरा बेन के बेटे पीएम मोदी की हीरे वाली को देखने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। बाद में इस हीरे को नीलाम किए जाने की चर्चा है।

सूरत में पिछले साल पीएम मोदी ने डायमंड बोर्स को जब शुभारंभ किया था तो उन्होंने कहा था कि कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बोर्स वन स्टॉप सेंटर है। आज सूरत डायमंड बोर्स के रूप में एक इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बनकर तैयार हो गया है। रॉ डायमंड हो, पालिश्ड डायमंड हो या लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर बनी बनाई जूलरी, आज हर तरह का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। सूरत में हाल के सालों में लेबग्रोन डायमंड का काम शुरू हुआ है, हालांकि इस मामले में अभी भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 15 फीसदी है।

गुजरात में फर्जी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल सील, डॉक्टर अपने नर्सिंग स्टॉफ के साथ मौके से फरार

अहमदाबाद। राजकोट में फर्जी स्कूल पकड़े जाने के बाद अहमदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में फर्जी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने सील किया है। फर्जी डाक्टर इस अस्पताल का संचालन कर रहा था। हॉस्पिटल को सील करने से पहले वह मेडिकल उपकरण लेकर अपने स्टाफ के साथ भाग गया।

अहमदाबाद जिला मुख् चिकित्सा अधिकारी डा शैलेष परमार जिले में झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने डा. मेहुल चावडा की अनन्या हॉस्पिटल को सील किया था। शुक्र वार को उसी के सामने चल रही मल्टीस्पेशियलिटी मोरैया हास्पिटल पर छापा मारा गया। इस कार्यवाही से पहले फर्जी डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ भागने में कामयाब रहे।

राजकोट में फर्जी स्कूल पकड़े जाने के बाद अहमदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में फर्जी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने सील किया है। फर्जी डाक्टर इस अस्पताल का संचालन कर रहा था। अहमदाबाद जिला मुख् चिकित्सा अधिकारी डा शैलेष परमार जिले में झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने डा. मेहुल चावडा की अनन्या हॉस्पिटल को सील किया था।

गौरतलब है कि पिछले दिनों राजकोट जिला प्रशासन ने गौरी प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से चल फर्जी स्कूल को सील किया था। यहां अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा था। ध्यान रहे कि बीते साल गुजरात में एक फर्जी टोल नाका पकड़ा गया था। उसके बाद एक फर्जी सरकारी कार्यालय चलने का मामला सामने आया था।

विद्यार्थियों से भरी स्कूल वैन में लगी आग, समय रहते कार्यवाही से बड़ी दुर्घटना टला

मेहसाणा (ईएमएस) जिले के बहुचराजी में विद्यार्थियों से भरी स्कूल वैन में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। हालांकि समय रहते वैन में सवार सभी बच्चों को उतार लेने से बड़ी दुर्घटना टल गई। साथ ही आग विकराल स्वरूप धारण करे उससे पहले उस पर काबू पा लिया गया।

जानकारी के मुताबिक मेहसाणा जिले के बहुचराजी में विद्यार्थियों को लेकर जा रही एक स्कूल वैन में बैटरी में स्पार्क होने से आग लग गई। आग लगते ही वैन में सवार सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित उतार लेने से बड़ी दुर्घटना टल गई। आग की घटना के बाद आसपास के लोग जमा हो गए और वैन में मौजूद फायर के साधनों से आग पर काबू पा लिया।

46 ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के 92 कोच लगाए गए हैं, 22 अन्य ट्रेनों में भी कोचों की संख्या बढ़ाने की योजना

भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को सुविधा के लिए लम्बी दूरी की 46 विभिन्न महत्वपूर्ण ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या में विस्तार किया गया है। इन ट्रेनों में 92 नए सामान्य श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। इसके अलावा 22 अन्य ट्रेनों की भी पहचान करने और उनमें अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच जोड़ने की योजना बनाई गई है।

निम्नलिखित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है: 1. 15634/15633 गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, 2. 15631/15632 गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस, 3. 15630/15629 सिलघाट टाउन ताम्बरम नागांव एक्सप्रेस, 4. 15647/15648 गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, 5. 15651/15652 गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस, 6. 15653/15654 गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस, 7. 15636/15635 गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस, 8. 12510/12509 गुवाहाटी बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 9. 15909/15910 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस, 10. 20415/20416 वाराणसी इंदौर सुपर-फास्ट एक्सप्रेस, 11. 20413/20414 काशी महाकाल वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12. 13351/13352 धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस, 13. 14119/14120 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, 14. 12976/12975 जयपुर मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 15. 17421/17422 तिरुपति कोल्लम एक्सप्रेस, 16. 12703/12704 हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, 17. 12253/12254 बेंगलुरु भागलपुर एक्सप्रेस, 18. 16527/16528 यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस, 19. 16209/16210 अजमेर मैसूर एक्सप्रेस, 20. 12703/12704 हावड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 21. 16236/16235 मैसूर तूतीकोरिन एक्सप्रेस, 22. 16507/16508 जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस, 23. 20653/20654 केएसआर बेंगलुरु सिटी बेलगावी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 24. 17311/17312 चेन्नई सेंट्रल हुबली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 25. 12253/12254 बेंगलुरु भागलपुर अंग एक्सप्रेस, 26. 16559/16590 बेंगलुरु सिटी सांगली रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस, 27. 09817/09818 कोटा जंक्शन दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 28. 19813/19814 कोटा सिरसा एक्सप्रेस, 29. 12972/12971 भावनगर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 30. 19217/19218 बांद्रा टर्मिनस वेरावल सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, 31. 22956/22955 मुंबई बांद्रा भुज कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 32. 20908/20907 भुज दादर सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 33. 11301/11302 मुंबई बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस, 34. 12111/12112 मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 35. 12139/12140 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस

इन सभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने से आम जनता की यात्रा काफी आरामदायक होगी।

वलसाड में ४ इंच बरसात से निचले इलाकों में जलभराव

अहमदाबाद, १३ जुलाई ।

मौसम विभाग ने अगले ५ दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। खासकर तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण गुजरात में शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। जिसके चलते वलसाड के गणदेवी में साढ़े चार इंच, व्यारा में ढाई इंच और नवसारी शहर में दो इंच बारिश हुई है।

गणदेवी में चार इंच बारिश होने से निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। शहर की कई सड़कें बंद हो जाने से जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। गणदेवी में चार घंटे में साढ़े छह इंच बारिश हुई। तो जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आता है। इसके साथ ही जलालपोर का खरसाड गांव भी जलमग्न हो गया है। गांव की मुख्य सड़क के ऊपर से नदियां बहने लगी हैं। आज सुबह ६ बजे से दोपहर १२ बजे तक राज्य के ४८ तालुकाओं में बारिश की सूचना है।

वलसाड जिले में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. ऐसे में जिले की ११ सड़कें बंद हो गई हैं। बाढ़ के कारण कम से कम ११ निचले स्तर के पुलों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। जलभराव के कारण वलसाड शहर के दो प्रमुख अंडरब्रिजों की भी मरम्मत की गई है। प्रशासन ने नदी के किनारे न जाने की अपील की है। नवसारी और उपरवासना जिलों में भारी बारिश के कारण नदियाँ उफान पर हैं। डांग जिले में भारी बारिश के कारण कावेरी नदी का जलस्तर एक फुट से अधिक बढ़ गया है। नदी में पानी बढ़ने से अटालिया उंडैच को जोड़ने वाला पुल बहने की कगार पर है. यदि यह पुल डूब गया तो कई गांवों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा।

दोपहर करीब चार बजे अहमदाबाद शहर में भारी बारिश हुई। तो कई जगह पानी भर गया। उधर, जूनागढ़ और अमरेली में भी बारिश हुई है। शुक्रवार की सुबह ६ बजे से शाम ४ बजे तक राज्य के १०० तालुकाओं में बारिश की खबर है। राज्य में आज सुबह ६ बजे तक सीजन की औसत बारिश २६.३२ फीसदी दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के बारिश के पूर्वानुमान के मुताबिक महिसागर जिले में बादल छाये हुए हैं। लंबे अंतराल के बाद नावाड़ा में बारिश हुई है, जिससे माहौल ठंडा है, वहीं किसानों में भी खुशी देखी जा रही है। आणंद जिले के खंभात में सुबह से धीमी गति से बारिश हुई, जिसके बाद दोपहर में बारिश की तीव्रता अचानक बढ़ गई। खंभात शहर और तालुका में अच्छी बारिश हो रही है।

सुरेंद्रनगर जिले के खारघोड़ा गांव के करीब ६० से ६२ साल के एक अधेड़ की नदी में डूबने से मौत हो गई। दसाडा विधायक, मामलतदार और उप मामलतदार सहित सरकारी कर्मचारी तुरंत खारघोड़ा गांव पहुंचे।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः क